

स्मरण पत्र

अति आवश्यक / फैक्स द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 2(2)15/विधि/प्रमुवस/ 1763-79  
निमित्त,

दिनांक: 25/02/2016

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सिल्वीकल्चर) जयपुर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर

मुख्य वन संरक्षक,

वन्यजीव, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर

परियोजना, कोटा/विभागीय कार्य, जयपुर/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु, जयपुर

विषय: Reduction in pendency through implementation of State Litigation Policy.

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्रांक 268-85 दिनांक 14.01.16 एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
का पत्रांक प0 12 (8)राज/वाद/10, पार्ट-गा जयपुर दिनांक 13.01.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सन्दर्भित पत्र की छायां प्रति संगलन कर लेख है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र का पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर दिनांक 18.01.16 तक भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया था। सूचना आवश्यक होने के कारण पत्र का दिनांक 14.01.16 को पत्र का फैक्स भी कराया गया। परन्तु चाही गई सूचना आदिनांक तक आपसे अप्राप्त है।

अतः चाही गई सूचना तत्काल 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि विधि एवं विधिक कार्य विभाग को सूचना भिजवाई जा सकें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार कृ.प.उ.

भवदीय,

(ए.के.सिंह)

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि,

राजस्थान, जयपुर।

DLR

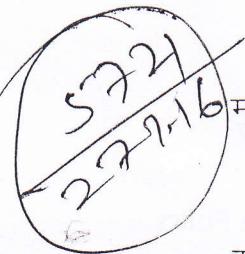
रा नस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प० 12 (8)राज / वाद / 10,पार्ट-गा  
समस्त अतिः मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव  
/ शासन सचिव.....

जयपुर, दिनांक 13-1-2016

विषय:- Reduction in Pendency through implementation of State Litigation Policy.

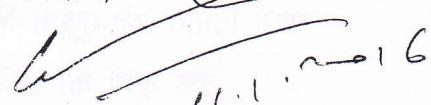
संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.12.15

 महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के साथ उप शासन सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन पश्चात् विचाराधीन प्रकरणों में कमी (Reduction in Pendency through implementation of State Litigation Policy) के क्रम में उनके द्वारा निर्धारित प्रोफार्म संलग्न कर आपके विभाग से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र में अंकित कर भिजवाने हेतु लिखा गया था किन्तु अभी तक आपके विभाग से संबंधित सूचना अप्राप्त है। अतः चाही गई सूचना अतिशीघ्र (अधिकतम 7 दिवस के भीतर) इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करने का श्रम करें।

राजस्थान सरकार

भवदीय,

  
11.1.2016

(धर्मदत्त शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

पत्र प्रधान मुख्य वन सरकार  
राजस्थान राज्यपाल की आवश्यक  
कार्यालय में अंकित है।  
प्रधान मुख्य वन सरकार  
उप विधि परामर्शी

ALF  
प्रधान मुख्य वन सरकार  
राजस्थान राज्यपाल की आवश्यक  
कार्यालय में अंकित है।  
प्रधान मुख्य वन सरकार  
उप विधि परामर्शी

312  
28.1.16 F9

**Form for Assessment of Impact of Implementation of State Litigation Policy  
of the State:**

**Reduction of Pendency of Cases in High Court in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).**

Particulars	Number of Cases pending in High Court as on 01.07.2014 which were added during 01.07.2014 to 31.12.2014.	Number of Cases in which State Government was a party	Number of cases disposed of by High Court as on 01.07.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases pending in High Court as on 31.12.2014	Remarks if any*
1. Pending cases 0 to 1 year old						
2. Pending cases 1 to 5 years old						
3. Pending cases more than 5 years old						
Total						

**2. Reduction of Pendency of Cases in Subordinate Courts in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).**

Sr. No.	Particulars	Number of Cases pending in Subordinate Courts as on 01.07.2014 which were added during 01.07.2014 to 31.12.2014.	Number of Cases in which State Government was a party	Number of cases disposed of by Subordinate Courts as on 01.07.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases pending in Subordinate Courts as on 31.12.2014	Remarks if any*
1.	Pending cases 0 to 1 year old						
2.	Pending cases 1 to 5 years old						
3.	Pending cases more than 5 years old						
Total							

\*In case it has not been possible to reduce pendency of Cases in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant), the reasons, if any, for the same could be mentioned under remarks column.

**3. Special Measures, if any, taken by the State Government for reduction in pendency of Cases in which State Government, was a party (petitioner or respondent or appellant).**

\*\*\*\*\*